Riot-Affected Villages and Families in Gonda, U.P.

528. SHRI SANTOSH BAGRODIA:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of villages and families affected due to riots in Gonda villages in U.P.; and

(b) what steps Government have taken to help the affected people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) 32 villages/hamlets, were affected, (in which 865 houses were burnt). The State Govt, distributed a sum of Rs. 75.91 lakhs to the riot-affected families/persons.

Indian Navy Ships Missing from the Bay of Bengal

529. SHRI SANTOSH BAGRODIA:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of ships belonging to the Indian Navy lost/drowned or missing during the last five years in the Bay of Bengal; year-wise;

(b) the number of people died/missing in these accidents; year-wise; and

(c) whether the Indian Navy has taken any steps to avoid such incidents in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH): (a) Only one ship, INS Andaman, was lost in a sinking accident in August 1990 in the Bay of Bengal, in the last five years.

(b) Fifteen persons have been reported massing in this accident; bodies of two persons were later recovered

(c) Adequate arrangements exist to prevent such accidents at sea. The findings of the Inquiry Board, ordered to go into the accident, are being studied. Such further measures, as appear necessary, will be taken, keeping in view the findings of the Board.

Ram Janambhoomi-Babri Masjid Issue

530. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have since contemplated any efforts to solve the disputed Ram Janambhoomi-Babri Masjid issue;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government would accept and implement the verdict of the court in the matter; and

(d) if so what is the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (d) Efforts to resolve the Ram Janambhoomi- Babri Masjid despute have been continuing. Government has succeeded in Holding a joint sitting of V.H.P. and Babri Masjid Action Committee. Both these organisations have submitted their evidences to substantiate their claims on the disputed site to the Government. Government have made available the copies of relevant documents to the parties concerned. The next meeting is scheduled to be held on January 10, 1991.

महाराष्ट्र में चीनी-कारखाने खोलने के लिए प्रार्थना पत्र

531. श्री विठ्ठल राव रामराव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में चीनी-कारखाने खोलने के लिए बहुत

से प्रार्थना-पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार इन आवेदनपत्रों को कब तक निपटाने का विचार रखती है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की नई नीति क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : विवरण

(क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में चीनी के नये कारखाने लगाने के लिए 139 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनपत्र तथा चीनी के मौजूदा कारखानों में पर्याप्त विस्तार करने के लिए 11 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र निपटान के लिए लंबित पड़े हैं।

(ख) लंबित आवेदनपत्रों के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किए जाते हैं, जब तक कि सरकार ने उन पर कोई अंतिम निर्णय न ले लिया हो ।

(ग) आवेदनपत्रों को यथाशीघ्र निपटाने का सरकार का निरंतर प्रयास रहता है ।

(घ) ता: 23 जुलाई 1990 के प्रैस नोट सं. 4 (1990 शृंखला) के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के नये कारखानों के लिए लाइसेंस देने तथा चीनी के मौजूदा कारखानों में विस्तार करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी-सिद्धांत बनाये गये हैं :—

(1) प्रति दिन 2500 मी० टन गन्ना पेराई (टी सी डी) की न्यूनतम किफायती क्षमता हेतु नये चीनी कारखानों को लाइसेंस दिया जाता रहेगा । इस प्रकार की क्षमता की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । गन्ने की उपलब्धता की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों अथवा अविकसित क्षेत्रों के लिए न्यूनतम किफायती क्षमता में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

(2) चीनी के नये कारखानों के लिए लाइसेंस इस शर्त पर जारी किए जायेंगे कि 15 कि मी की त्रिज्या दूरी में कोई चीनी मिल नहीं है । आवेदक को गन्ने के विकास के लिए कोई प्रमाण-पत्र/स्वीकृति पत्र देने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) सभी नये लाइसेंस इस शर्त के साथ जारी किए जायेंगे कि गन्ने का मूल्य चीनी में खांड की मात्रा के आधार पर देय होगा ।

(4) अन्य बातों के समान रहने पर लाइसेंस देने के लिए निजी क्षेत्र की तुलना में सहकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से मिले प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी ।

(5) नये चीनी कारखानों को लाइसेंस मंजूर करते समय शीरा अर्थात् औद्योगिक अलकोहल आदि के प्रयोग के लिए डाउनस्ट्रीम एककों को औद्योगिक लाइसेंस तुरंत दिए जायेंगे ।

(6) 2500 टी सी डी से कम की क्षमता वाले कारखानों को उपर्युक्त किफायती क्षमता तक विस्तार करने के लिए प्राथमिकता दी जायगी ।

Kick-backs paid in getting Maruti dealerships

532. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Weekly Magazine "The Week" dated 9th September, 1990 under the caption "Monkey Business in Maruti" wherein an allegation has been made regarding crores of rupees kickbacks being paid to politicians and the company officers to get the Maruti dealership; if so, the details thereof; and

(b) whether in view of large scale criticism against awarding dealership